बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 184 ● नई दिल्ली ● वीरवार 07 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

भाटी माइंस के जंगल में 14 वर्षीय बच्चे का शव मिला, गला घोंटकर हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस जंगल में एक 14 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। प्राथमिक जांच में गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना भाटी माइंस के घने जंगल वाले इलाके में हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। किशोर की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है, लेकिन उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है। शव मिलने के तरीके से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है।

वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा-जुर्माना

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल और असम में शानदार जीत के बाद, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगान वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी - इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश - के चुनाव परिणामों के बाद मंगलवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत बताते हुए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संबंधी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि वंदे मातरम को भी उसी कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके जो वर्तमान में राष्ट्रगान को संरक्षण प्रदान करता है। इसके लागू होने के बाद, वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी प्रकार का अनादर या बाधा डालना संज्ञेय

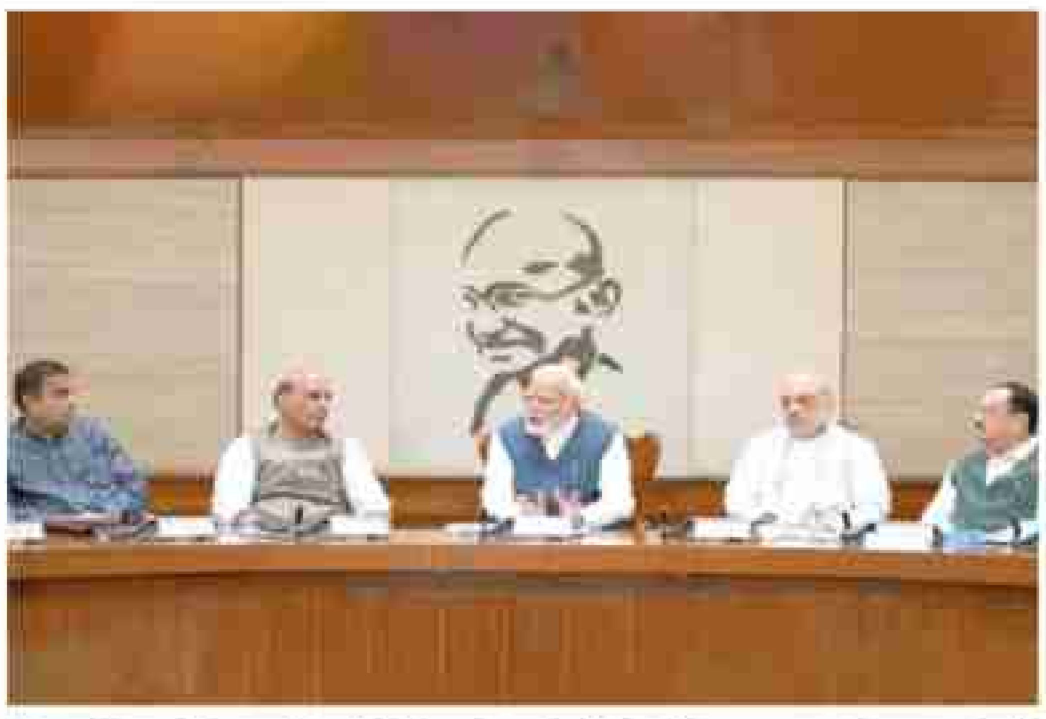

अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधन वंदे मातरम पर भी इन प्रावधानों को लागू करेगा, जिसका अर्थ है कि उल्लंघन करने पर भी इसी तरह के कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे बाधित करता है, उसे 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। बार-बार अपराध करने वालों को कम से कम एक साल की कैद की सजा हो सकती है। उम्मीद है कि संशोधन लागू होने के बाद ये प्रावधान राष्ट्रगान पर भी लागू होंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक इतिहास में विशेष स्थान है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश इस प्रतिष्ठित रचना की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिससे मंत्रिमंडल के इस निर्णय का प्रतीकात्मक महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के अनादरपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए 2005 में भी इसी प्रकार के संशोधन किए गए थे। पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में हुई एक विशेष चर्चा के दौरान भी वंदे मातरम को समान दर्जा देने की मांग उठाई गई थी, जो इसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। प्रस्तावित संशोधन को जल्द ही संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को कानूनी रूप से मान्यता देने और उनकी रक्षा करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

दिल्ली चुनाव में हार के डेढ़ साल बाद जगी कांग्रेस, फेरबदल की तैयारी में आलाकमान

नई दिल्ली । दिल्ली में कांग्रेस संगठन को नई दिशा देने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं. शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद प्रदेश इकाई में कई अहम नियुक्तियां की गई हैं, जिनसे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल की स्वीकृति के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है. देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव नियुक्त किए गए हैं. साथ ही 31 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का भी गठन किया गया है, जो भविष्य की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी. पूर्व विधायक और वर्तमान में मीडिया विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज को संगठन महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संघर्ष के दौर में निभाई गई सक्रिय भूमिका को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है. उन्हें दिल्ली कांग्रेस का एक मजबूत रणनीतिकार माना जाता रहा है. नई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में संतुलन और समावेशिता का पूरा ध्यान रखा गया है. टीम में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, युवा, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और सेवा दल के सदस्यों को शामिल किया गया है. पार्टी का कहना है कि सभी धर्म, जाति और वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, ताकि संगठन व्यापक स्तर पर मजबूत हो सके. देवेन्द्र यादव ने नई टीम को लेकर भरोसा जताया है कि यह संगठन को नई ऊर्जा देगी. उन्होंने कहा कि यह टीम याद्दा क्षमता के साथ काम करेगी और दिल्ली में कांग्रेस के जनाधार को फिर से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी. आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने में यह टीम कारगर साबित होगी.

भाजपा ने लगाया कांग्रेस पर सहयोगियों को इस्तेमाल करके फेंकने का आरोप

नई दिल्ली । भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सहयोगियों को इस्तेमाल करके फेंकने का आरोप लगाया है, जिसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु में डीएमके से दूरी बनाना है। कांग्रेस द्वारा विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के फैसले के बाद, पुराने सहयोगी डीएमके ने इसे धोखा बताया है, जिससे इंडिया गठबंधन में दरार और गहरी हो गई है। कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को पार्टी पर अपने सहयोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपने गठबंधन सहयोगियों का उपयोग करके छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी और अब डीएमके जैसी पार्टियों का उपयोग करके उन्हें त्याग दिया है, और भारतीय गठबंधन को एक स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि से रहित बताया। एएनआई से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। वे गठबंधन सहयोगियों, क्षेत्रीय पार्टियों का उपयोग करके उन्हें त्याग देते हैं। हमने देखा है कि उन्होंने आरजेडी का उपयोग किया और उसे त्याग दिया। उन्होंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट का उपयोग किया और उन्हें त्याग दिया। अब उन्होंने डीएमके का उपयोग किया, सीटें हासिल कीं, और उन्हें त्याग रहे हैं। इसलिए भारतीय गठबंधन एक लक्ष्य और दूरदृष्टि वाला गठबंधन नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर क्षेत्रीय सहयोगियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और इंडी गठबंधन को भ्रम, विभाजन और भ्रष्टाचार से भरा हुआ बताया, जो सत्ता की लालसा से प्रेरित है। पूनावला ने कहा कि यह भ्रम, विभाजन, भ्रष्टाचार, सत्ता की महत्वाकांक्षा और मोदी जी के प्रति जुनून का गठबंधन है। इसलिए वे एक साथ आए। लेकिन अब, इंडी गठबंधन कहां है? क्या यह बंगाल चुनाव में था? क्या यह केरल चुनाव में था? यह पूरे देश में कहां है? क्या आपको इंडी गठबंधन दिखाई देता है? महाराष्ट्र और बिहार में भी उनका गठबंधन टूट रहा है। इसलिए डीएमके और कांग्रेस का तीन तलाक हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की लालसा है। उन्होंने डीएमके का इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और कांग्रेस का व्यवहार हमेशा ऐसा ही होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, यह एक परजीवी की तरह है। यह सिर्फ वोट बैंक के लिए क्षेत्रीय पार्टी का इस्तेमाल करती है, और एक बार वोट बैंक मिल जाने पर, यह आगे बढ़ जाती है। इस बीच, भारत गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस और डीएमके के बीच सबसे लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों में से एक अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की मंजूरी दे दी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए इस फैसले को दूरदर्शिता की कमी वाला बताया और उन पर भारत के सहयोगी दलों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का यह रुख बहुत ही अदूरदर्शी और संकीर्ण है, जिसका उन्हें पछतावा होगा। 2029 के बड़े चुनाव आ रहे हैं, जिनमें हमें पूरा भरोसा है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अब कांग्रेस के इस फैसले से वे एक बहुत ही अस्थिर सहयोगी बन गए हैं। पूरे देश में यही धारणा बन गई है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार, विजय के नेतृत्व वाली पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनावों में बहुमत के लिए 10 सीटें कम मिलने के बाद, कांग्रेस ने सर्वसम्मति से राय में सरकार बनाने के लिए तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) का समर्थन करने का फैसला किया है।

मुंडका में सिस्टम की लापरवाही ने ली 2 साल की मासूम की जान, खुले नाले में गिरकर मौत

नई दिल्ली । दिल्ली में बुनियादी ढांचे की अनदेखी एक बार फिर एक मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ी. बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में खुले नाले में गिरने से दो साल की एक बच्ची की मौत ने सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सफाई के बाद नाले को ढंकने में बरती गई लापरवाही ने एक मां-बाप की इकलौती संतान को उससे छीन कर जिंदगी भर न भूलने वाला गम दे दिया. बाहरी दिल्ली स्थित मुंडका इलाके के 60 फुटा रोड स्थित राज मंदिर के सामने रहने वाले विकास अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे. इसी दौरान उनकी दो साल की बेटी अंशिका घर के बाहर खेल रही थी. जो खेलते-खेलते उनकी नजरों से ओझल हो गई, और परिवार में हड़कंप मच गया.

परिजनों ने तुरंत आसपास खोजबीन शुरू की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की और उन्हें भी साथ लेकर उसकी तलाश में जुट गए. करीब आधे घंटे बाद घर के पास ही खुले नाले के भीतर बच्ची के गिरने का पता चला. तुरंत ही परिजनों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत पानी में डूबने के कारण हुई. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है.

नाले की सफाई के बाद नहीं लगाया गया ढक्कन

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब एक माह पहले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नाले की सफाई करवाई थी. सफाई के दौरान नाले के ऊपर से ढक्कन हटाया गया, लेकिन बाद में उसे दोबारा बंद नहीं किया गया. इसी लापरवाही ने नाले को खुले खतरे में बदल दिया. बताया जा रहा है कि यह नाला करीब 60 फुट के डेड-एंड हिस्से से जुड़ा है, जहां से पानी का बहाव दिल्ली से हरियाणा की ओर मुड़ता है. इस संरचना के कारण नाले में गिरने के बाद उससे बाहर निकल पाना लगभग असंभव सा हो जाता है जो हादसों को और भी खतरनाक बना देता है.

शव घर पहुंचते ही फूटा लोगों का गुस्सा

बताया जा रहा है कि, मृत बच्ची के पिता विकास की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी और अंशिका उनकी इकलौती संतान थी. जिसे विभागीय लापरवाही ने उनसे छीन लिया. पोस्टमार्टम के बाद जब बच्ची का शव घर लाया गया तो इलाके में आक्रोश फैल गया. स्थानीय लोगों ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि यदि सफाई के बाद नाले को ठीक से ढक दिया जाता तो यह हादसा नहीं होता. लोगों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. अधिकारियों ने जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा देकर स्थिति को नियंत्रित किया.

पहले भी हो चुके हैं हादसे, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के हादसे इलाके में पहले भी हो चुके हैं. इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है.

एसी ब्लास्ट हुआ या कोई चूक, कारण तलाश रहीं एजेंसियां; छानबीन में इमारत में मिलीं कई खामियां

दिल्ली । विवेक विहार के पॉश बी-ब्लॉक में चार मंजिला इमारत में लगी आग में नौ लोगों की जान चली गई थी। पुलिस के अलावा तमाम एजेंसियां आग की वजहों का पता लगाने में जुटी हैं। मंगलवार को इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर (विद्युत निरीक्षक) व दिल्ली नगर निगम की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर ने इमारत की बेहद बारीकी से पड़ताल की। सूत्रों ने कहा कि इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा कि बिल्डिंग में हादसे के समय कितना इलेक्ट्रिसिटी लोड चल रहा था। इसके अलावा बिल्डिंग में लगे बिजली के मीटर पर कितना लोड मंजूर था। माना जा रहा कि तय लोड से यदि यादा लोड चल रहा था तो आग की संभावना बनी हुई थी। वहीं मामले की जांच कर रही टीम के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच में यह पता चला कि आग इमारत के पिछले हिस्से में दूसरी मंजिल की बालकनी से शुरू हुई। आशंका है कि यहीं पर एसी ब्लास्ट हुआ और आग ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ी। बाद में हादसे में कई लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर नगर निगम की टीम ने इमारत में हुए अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने के लिए पहुंची थीं। टीम ने पूरी इमारत का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि बिल्डर ने स्टिल्ट पार्किंग के अलावा अवैध रूप से इमारत में बेसमेंट का भी निर्माण किया था। इसके अलावा अवैध रूप से पीछे की बालकनी को लोहे का जाल लगाकर कवर किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली फायर सर्विस की टीम को भी बुलाया गया था। किसी कारण टीम मौके पर नहीं पहुंची। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को दमकल की टीम अपनी जांच के लिए आएगी। मंगलवार को क्राइम टीम के अधिकारी एक बार फिर जांच के लिए मौके पर पहुंचे। शाहदरा जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आग के सही कारणों का पता करने में अभी कुछ और दिन का समय लगेगा। एफएसएल के अलावा दूसरे विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंपेंगे। इसके बाद ही आग की वजहों तक पहुंचा जा सकेगा। जांच के बाद ही इमारत को दोबारा से रहने के लिए खोला जाएगा। हादसे में चली गई थी नौ लोगों की जान – विवेक विहार के पॉश एरिया बी-ब्लॉक में रविवार तड़के एक चार मंजिला मकान में आग लग गई थी। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई। करीब छह लोग जख्मी हो गए। पुलिस व दमकल की टीम ने 15 लोगों को ऊपरी मंजिलों से सुरक्षित निकाला। आग लगने के पीछे एसी ब्लास्ट को बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

जांच दल को इमारत में यह मिली खामियां

पूरी इमारत में आने-जाने के लिए एक ही जीने (सीढ़ियों) का इस्तेमाल।

सीढ़ियों की चौड़ाई कम, उसमें ममटी के पास कोई वेंटिलेशन भी नहीं।

इमारत में स्टिल्ट पार्किंग के साथ बेसमेंट और ऊपर चार मंजिलों का अवैध निर्माण। सीढ़ियों को पार्किंग के बीचों-बीच बनाया गया, पार्किंग में आग लगने ऊपर के लोग फंसे। पूरी इमारत में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं, न कोई सिलिंडर न कोई पानी का टैंक।

बंगाल में निर्ममता की हार, तुष्टिकरण पर प्रहार और विकास की बयार

पश्चिम बंगाल के जनादेश ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक, प्रभावी और परिणाम देने वाले नेतृत्व पर अडिग विश्वास रखती है। यह भरोसा किसी भावनात्मक लहर का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से दिख रहे सुशासन, पारदर्शिता और निरंतर विकास की ठोस बुनियाद पर खड़ा है। यह केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के भीतर वर्षों से पनप रहे आक्रोश, पीड़ा और बदलाव की आकांक्षा का सशक्त विस्फोट है। इस जनादेश में साफ दिखता है कि जनता ने भय की राजनीति को नकारते हुए भरोसे को अपनाया, तुष्टिकरण को ठुकराकर विकास को चुना और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर सुशासन को प्राथमिकता दी। बंगाल में यह जीत वास्तव में जनता की जीत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और खुले तुष्टिकरण के खिलाफ जनता लंबे समय से सड़कों पर थी। हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी, सबने इस व्यवस्था के खिलाफ मन बना लिया था। पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिन्दू समाज के साथ भेदभाव हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति ने सामाजिक संतुलन को बिगाड़ा और अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन देकर राज्य की पहचान और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए गए। हालात ऐसे बन गए थे कि कई इलाकों में हिन्दू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चुनाव के समय उन्हें वोट डालने तक से रोका गया, डराया-धमकाया गया। यह लोकतंत्र का अपमान था, लेकिन इस बार जनता ने इन सबका जवाब दिया है। ममता बनर्जी की हताशा चुनाव से पहले ही दिखने लगी थी। एक भ्रष्ट निजी कंपनी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति का विरोध करना, ये सभी कदम इस बात के संकेत थे कि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका था। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और जनता ने अपना फैसला स्पष्ट रूप से सुना दिया। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार ने जिस तरह से विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसका असर हर राज्य में दिख रहा है। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां न केवल विकास हुआ है बल्कि जनता ने बार-बार उस पर मुहर लगाई है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना और वह भी पहले से अधिक, लगभग तीन-चौथाई बहुमत के साथ, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। असम में बुनियादी ढांचे से लेकर कानून-व्यवस्था तक हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसका परिणाम जनता के विश्वास के रूप में सामने आया है। इन विधानसभा चुनावों में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। राहुल गांधी एक बार फिर इस चुनाव में असफल नेता के रूप में सामने आए हैं। वह न तो इंडी गठबंधन को एकजुट रख पाए और न ही जनता के बीच कोई विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत कर पाए। चुनाव परिणामों के समय उनका विदेश में होना यह दर्शाता है कि वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इंडी गठबंधन अब केवल नाम का गठबंधन रह गया है, जिसका भविष्य अंधकारमय दिखता है। तमिलनाडु में वर्षों से जो लोग सनातन संस्कृति का अपमान करते आए, जिन्होंने हिन्दू आस्थाओं को निशाना बनाया, दीपम जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधाएं डालीं और धर्म-भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की। जनता ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है। सनातन संस्कृति की तुलना डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से करने वाली मानसिकता को जनता ने नकार दिया है। यह बदलाव धीरे-धीरे ही सही, लेकिन स्थायी रूप से उभर रहा है। पुडुचेरी में भी भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। भले ही यह प्रतिशत में कम दिखे, लेकिन यह संकेत स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी वैचारिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। केरल में भी भाजपा का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। भले ही अभी वहां सत्ता तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन जनता के बीच वैचारिक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि देश का हर कोना अब विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं का संघर्ष और बलिदान छिपा हुआ है। पिछले कई वर्षों में, खासकर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की हिंसा और उत्पीड़न का सामना किया, वह अभूतपूर्व था। हजारों कार्यकर्ताओं को बेघर होना पड़ा, कईयों के घरों में आग लगा दी गई, दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक गंवाई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा किए गए इन अत्याचारों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और मजबूती से संघर्ष किया। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि विचारधारा और लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष था। आज जब बंगाल में कमल खिला है, तो यह केवल एक पार्टी की जीत नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने अपने खून-पसीने से इस जमीन को सींचा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर यह जीत विशेष महत्व रखती है। यही वह भूमि है जहां से वैकल्पिक राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी गई थी। आज उसी धरती पर भाजपा का परचम लहराना, उस विचारधारा की जीत है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानती है। यह जनादेश लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और सबसे बढ़कर बंगाल की जनता की जीत है। यह संदेश साफ है, जो सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, जो भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण में डूबी होती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो सरकार विकास, सुशासन और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है।

भारत-नेपाल लिपुलेख विवाद

पड़ोसी देश नेपाल की घरेलू राजनीति भारत के साथ उसके संबंधों में बार आड़े आती रही है। भारत और नेपाल में भी सीमा विवाद का अपना इतिहास जटिलताओं से मुक्त नहीं है। नेपाल के राजनीतिक दलों ने सीमा बिन्दुओं का राजनीतिक समाधान करने की बजाय अपने घरेलू राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। सीमाओं के ऐतिहासिक महत्व को जानना भी जरूरी है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी लेकिन बालेन शाह ने लिपुलेख विवाद को हवा देकर राष्ट्रवादी कार्ड खेल दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाशमानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। काठमांडौ ने इस संबंध में भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाल ने भारतीय राजदूत को इस मामले में तलब भी किया है। नेपाल के दावों को लेकर भारत ने भी सख्त रुख अपनाया है। भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर का पुराना रास्ता रहा है और इस रास्ते से यात्रा दशकों से होती रही है। जहां तक इलाके के दावों की बात है भारत ने हमेशा कहा है कि ऐसे दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। लिपुलेख दर्रे के दावों को इस तरह एकतरफा बनावटी तरीके से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। यद्यपि नेपाल और भारत ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में की गई सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी भारत-नेपाल संबंधों में तनाव के बीच यह मुद्दा उठाया था। बाद में के.पी. शर्मा ओली ने भी इस मुद्दे को काफी हवा दी। उन्होंने तो लिपुलेख दर्रे, लिम्पिया धुरा दर्रे और काला पानी क्षेत्रों पर नेपाल का दावा जताते हुए देश का नया मानचित्र भी जारी कर दिया था। भारत ने तब भी नेपाल के नए नक्शे को खारिज करते हुए नेपाल के दावे को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर है। सन् 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला-लिपुलेख सड़क का उद्घाटन करने के बाद विरोध तेज हो गया। यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क धारचूला के घटियाबगढ़ से शुरू होकर लिपुलेख में समाप्त होती है। नेपाल का दावा है कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्षेत्र को लेकर नेपाल में तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के.पी. ओली का पुतला जलाकर उन पर भारतीय परियोजना का मुकाबला करने के लिए समय पर कदम न उठाने का आरोप लगाया। नेपाल में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री ओली की इस बात के लिए आलोचना की कि वे शासन में अक्षमता या कोविड-19 से निपटने के अप्रभावी उपायों की आलोचनाओं को दबाने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। फिर भी, अधिकांश लोगों ने राष्ट्रवाद की आवाज का समर्थन किया और सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की सराहना की। नेपाल में लिपुलेख दर्रे का मुद्दा वहां की जनता के लिए भावनात्मक मुद्दा बन चुका है और सरकारों का ऐसे मुद्दों पर जनभावनाओं के विपरीत जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के धर्म प्रेमी लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक और आस्थावान मुद्दा है। हर साल श्रद्धालुओं का जत्था कैलाश मानसरोवर की दुर्गम और कठिन यात्रा पर जाता है। इस बार बालेन शाह सरकार का अंदाज कुछ अलग है, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ-साथ चीन को भी अपने लपेटे में ले लिया है। जबकि पहले के.पी. शर्मा ओली ने सिर्फ भारत से ही आपत्ति जताई थी और उन्होंने नेपाल को पूरी तरह से चीन की गोद में डाल दिया था। बालेन शाह ने इस संवेदनशील मुद्दे कोउठाकर अपनी छवि को चमकाने का ही प्रयास किया है, जो न तोऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही न्याय संगत। कैलाश मानसरवर यात्रा में अड़ंगा लगाकर उन्होंने कोई राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया है। भारत से संबंधों में कड़वाहट पैदा कर नेपाल को नुकसान ही होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई कूटनयिक समाधान निकलता है और यात्रा क्या मोड़ लेती है।

सम्पादकीय...

पश्चिम बंगाल 2026 के परिणामों का उत्तर प्रदेश 2027 पर डिकपलिंग प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा

राष्ट्रीय राजनीति में एक आम धारणा यह होती है कि एक बड़े राज्य (जैसे पश्चिम बंगाल) में प्रचंड जीत का सुनामी प्रभाव आगामी चुनावों (जैसे उत्तर प्रदेश) को एकतरफा बना सकता है। हालांकि, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और चुनावी सांख्यिकी का एक सूक्ष्म विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि दोनों राज्यों की राजनीतिक तासीर, ऐतिहासिक विकास, सामाजिक संरचना और तात्कालिक चुनावी समीकरणों में बुनियादी और अपरिवर्तनीय अंतर है। इसलिए, पश्चिम बंगाल के परिणाम उत्तर प्रदेश में डिकपल्ड (Decoupled - अलग-थलग) रहेंगे और उनका कोई सीधा, यांत्रिक या मनोवैज्ञानिक असर यूपी के 2027 चुनावों पर नहीं पड़ेगा। 1. बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी ,टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी थी जो लगातार 15 साल से बंगाल में सरकार में थी ,वहीं यूपी में भाजपा के खिलाफ एंटीइनकंबेंसी है तो जिस तरह से टीएमसी को हराकर भाजपा सरकार में आई है बंगाल में उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी भाजपा को हराकर 2027 में सरकार बनाएगी। 2. PDA समाज इक जुट होकर जिस तरह से 2024 में भाजपा को यूपी में हराया था वही फॉर्मूला अब 2027 में भी काम करेगा क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरह से यूपी में बीजेपी की हार हुई थी वो केवल केन्द्र सरकार का फेल्योर नहीं था क्योंकि बीजेपी के प्रदेश सरकार से PDA समाज में काफी आक्रोश में था। 3. यूपी में SIR का असर बंगाल से कम पड़ने का संभावना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने एसआईआर 2.0 (SIR 2.0) लागू किया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की प्रकृति और पैमाने में भारी भिन्नता है। यूपी में 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं (कुल मतदाताओं का लगभग 13.2%) के नाम काटे गए, लेकिन इसके साथ ही 84.3 लाख (8.43 मिलियन) नए मतदाताओं को जोड़ा भी गया, जो पूरे देश में सर्वाधिक है 4.पश्चिम बंगाल चुनाव मुख्य रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर , नागरिकता संशोधन अधिनियम , जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अवैध घुसपैठियों जैसे वृहद राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लड़ा गया। बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, जहाँ इन मुद्दों का सीधा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव पूरी तरह से स्थानीय, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और रोजगार के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी रणनीति को अति-स्थानीय विषयों पर केंद्रित किया है—जैसे कमर्शियल एलपीजी के बढ़ते दाम, बिजली विभाग में स्मार्ट मीटरों की अनियंत्रित गड़बड़ियां, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षित सरकारी नौकरियों का खात्मा। और ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा के शासन में नौकरियां कम हो रही है और महंगाई आसमान छू रही है, जिससे युवा, बेरोजगार और आरक्षित वर्ग गहरे असंतोष में है। 5.उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति पूर्णतः भिन्न आधारों पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति मूल रूप से गहराई तक पैठी जातिगत अस्मिताओं पर आधारित है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज एकरलोफ के पहचान के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, जब पहचान (चाहे वह जाति हो या धर्म) बहुत मजबूत होती है, तो यह विकास की राजनीति या किसी भी राष्ट्रीय आह्वान पर हावी हो जाती है।

मोदी की झालमुड़ी का कमाल, जीत लिया बंगाल !

जिस प्रकार से ममता दीदी ने बंगाल में भय का भयानक वातावरण पैदा कर दिया था। भले ही ममता ने पूर्व में चुनाव जीते, मगर लोगों को प्रायः विस्मय होता था किस प्रकार से आग और ज़हर उगलने वाली चंडी देवी जैसी ममता दीदी कैसे जीत जाती हैं। कुछ भी हो, सलाम है, भाजपा के धुरंधर अंदाज़ से इलेक्शन लड़ने की कोशिशों को। कोई क्लोन भी नहीं कर सकता था कि बंगाल भाजपा की झोली में गिर जाएगा। अब जबकि भाजपा जीत चुकी है, उसे इस बात पर ध्यान देकर काम करना होगा कि आज़ादी के बाद से बंगाल को इंसाफ नहीं मिला है और इसकी दशा जर्जर है। पहले तो इस डबल इंजन सरकार को 75 साल के खड्डों को भरना होगा और साथ ही साथ मुस्लिमों का दिल भी जीतना होगा, जिनके क्षेत्रों से इस बार 45 प्रतिशत सीटें भाजपा ने जीती हैं जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने भी भाजपा को वोट दिए हैं।

फिरोज बख्त अहमद

यदि यह कहा जाए कि दिल जीतने की कलाकारी में भारतीय प्रधानमंत्री से बड़ा कलाकार कोई दूसरा नेता विश्व में नहीं। सड़क पर झालमुड़ी खाई और बच्चों के साथ, बंगाल के लोकप्रिय खेल फुटबॉल के कोच की भांति फुटबॉल खेल कर ममता दीदी का संपूर्ण खेला कर दिया। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ! दूसरी बात यह कि भारत के चुनाव इतिहास का भाजपा की बंगाल वाली जीत एक करिश्मा, एक अजूबा है। जहां अपने दौरों में मोदी और अमित शाह ने मेक बंगाल ग्रेट अगेन की भाषा से एक आम बंगाली के मन, मस्तिष्क और आत्मा को जीत लिया। इस बार बंगाल में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रांतों में भी भाजपा ने, केरल को छोड़ सबसे बढ़िया किया है। तमिलनाडु में भी स्टालिन का बोरिया-बिस्तर लपेटने में भाजपा का बड़ा रोल रहा। इस चुनाव को जीतने में जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जुगलबंदी रही, वह अटल बिहारी वाजपेयी के इसी कथन को जमीन पर लाया कि सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वास्तव में स्वयं भाजपा को ही नहीं पता कि कितना बड़ा किला बंगाल का उसने अपनी झोली में डाल लिया है। हां, जीतने के बाद शुभेंदु सरकार ने जिस प्रकार से मुसलमानों को दोष दिया कि उन्होंने दोनों हाथों से भर-भर कर ममता को वोट दिए, ठीक नहीं था, क्योंकि जीतने के बाद सभी को ग्रेसफुल होना चाहिए। इस प्रकार के बयानों से दूरियां और वैमनस्य बढ़ते हैं। बंगाल में मोदी-शाह की कार्पेट बॉम्बिंग ने प्रांत के विकास के लिए ममता के प्लेन फेल कर दिए। जिस प्रकार से अमित शाह ने अपनी मेहनत और कार्य प्रणाली द्वारा एक के बाद दूसरा चुनाव जीता है उससे उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि अपने परम मित्र मोदी के वे सब से दक्ष उत्तराधिकारी हैं। हां, मोदी का यह कमाल अवश्य है कि उन्होंने पिछले बारह वर्षों में भारत के डेढ़ करोड़ निवासियों को नरेंद्र मोदी में परिवर्तित कर दिया है। इन चुनावों का सबसे अच्छा पहलू यह रहा कि कहीं भी गोला-बारूद नहीं चला, कोई मारा नहीं गया जैसे बंगाल में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की जान विशेष रूप से बंगाल और केरल में ली जाती रही है।

बंगाल में ममता का खौफ था कि यदि उन्हें पता चल गया कि वोट तृणमूल को नहीं दिया गया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितने भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस विजय के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। जहां भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस जीत का श्रेय दे रही है, उसी प्रकार से हर बलिदानी कार्यकर्ता के परिवार को रोजगार और मदद से मालामाल कर देना चाहिए और उनकी प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए। ममता का जबानी जमा खर्च, 'मां, माटी, मानुष' सुनने में तो बहुत अच्छा था, मगर फेल इसलिए हुआ कि उसको उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा और न तो लोगों को रोजगार मिला और न ही सिक्योरिटी। वास्तव में ममता दीदी ने तीसरी पारी में जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड के रवैये से काफी दुखी किया। फिर जिस प्रकार धमकी भरी और घमंड से चूर भाषा प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेताओं के प्रति ममता दीदी बोलती चली आ रही हैं, आम लोगों में इसका विपरीत असर पड़ा। हैरानी की बात है कि जिन मुसलमानों ने दोनों हाथ भर कर तृणमूल को वोट दिए, ममता ने सिवाय नारेबाज़ी के टैंगे के उन्हें कुछ नहीं दिया। उनकी बस्तियां गंदगी और बड़बोले कुछ नहीं। उनके मकान, मदरसे आदि दयनीय स्थिति में हैं। बजाय स्कूलों क्रीड़ांगनों, उद्यानों आदि के उनकी बस्तियों में पुलिस स्टेशन अधिक हैं। भले ही भाजपा ने पूर्व में चुनाव जीते हों, मगर जो ऐतिहासिक विजय बंगाल में भाजपा को मिली है, उसे हम बंपर जीत का दर्जा नहीं तो क्या कहें। ममता राज की काफी त्रुटियां सामने आई हैं। संदेशखाली, बसीरहाट और आर जी कार मेडिकल कॉलेज जैसी हजारों बातें ऐसी हुईं कि जो जनता में चर्चा का विषय बनीं। जिस प्रकार से भाजपा की कैंडिडेट रत्ना देव नाथ के चेहरे पर तृणमूल के गुंडों ने थूका, वह वीभत्सपूर्ण कृत्य भी दुनिया ने देखा। यह भी देखा गया कि तृणमूल के बदमाशों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी औरतों को तृणमूल के नेताओं के घर भेजो। जिस प्रकार से ममता दीदी ने बंगाल में भय का भयानक वातावरण पैदा कर दिया था। भले ही ममता ने पूर्व में चुनाव जीते, मगर लोगों को प्रायः विस्मय होता था किस प्रकार से आग और ज़हर उगलने वाली चंडी देवी जैसी ममता दीदी कैसे जीत जाती हैं। कुछ भी हो, सलाम है, भाजपा के धुरंधर अंदाज़ से इलेक्शन लड़ने की कोशिशों को। कोई क्लोन भी नहीं कर सकता था कि बंगाल भाजपा की झोली में गिर जाएगा। अब जबकि भाजपा जीत चुकी है, उसे इस बात पर ध्यान देकर काम करना होगा कि आजादी के बाद से बंगाल को इंसाफ नहीं मिला है और इसकी दशा जर्जर है। पहले तो इस डबल इंजन सरकार को 75 साल के खड्डों को भरना होगा और साथ ही साथ मुस्लिमों का दिल भी जीतना होगा, जिनके क्षेत्रों से इस बार 45 प्रतिशत सीटें भाजपा ने जीती हैं जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने भी भाजपा को वोट दिए हैं।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि ला रहा है बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़के रीढ़ का काम करती है। सड़कों के निर्माण होने से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास बड़ी तेजी के साथ होता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र रहा है, जहाँ त्वरित आवागमन का अभाव था। पथरीला क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र वासियों को कई तरह की कठिनाई आती थी। प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए विशेष पैकेज दिये और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जहाँ बांधों, नलकूपों व तालाबों का निर्माण कराया है, वहीं पेयजल परियोजनायें पूर्ण कर ग्रामवासियों को जल आपूर्ति की जा रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराना, बुन्देलखण्ड वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसे उस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी सदैव याद रखेगी। यह एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के जनपद चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन से गुजरते हुए औरैया व जनपद इटावा में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे में जुड़ जाता है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे विकास का पहिया: प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है। बुन्देलखण्ड वासियों की हर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास करना सरकार का ध्येय है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना ध्यान वर्तमान सरकार ने दिया है, उतना पूर्व में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का शुभारम्भ एवं लोकार्पण देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह एक्सप्रेस-वे 296 किमी लम्बा है। यह जनपद चित्रकूट बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा जनपद में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे में मिलता है। अभी यह फोर लेन का है जिसे आगे चलकर 6 लेन भी बनाया जायेगा। इसमें चार रेलवे ओवर ब्रिज, 14 बड़ेपुल, सात रैम्प प्लाजा, 268 छोटेपुल, 18 फ्लाई ओवर और 214 अन्डरपास बने हैं। इस एक्सप्रेस-वे को समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से बुन्देलखण्ड के 138 ग्राम और औरैया व इटावा के 44 ग्रामों का सीधा जुड़ाव हो गया है। किसानों का हो रहा है फायदा: बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के बनने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल रहा है। किसानों को उनकी उपज की फसलें मण्डियों तक पहुँचाने में शीघ्रता हो रही है। स्थानीय फसल, फल, फूल, सब्जियों, दूध आदि जल्द खराब होने वाली फसलों को बाजारों, मण्डियों तक पहुँचने में शीघ्रता और ताजी होने पर सही मूल्य भी मिल रहा है। यदि किसान अपनी उपज को बाहर की मण्डियों, शहरों में बेचना चाहेगा तो उसका भी उसे फायदा मिलेगा। किसानों को खेती किसानी करने के लिए आवश्यक बीज, खाद आदि भी समय से मिलते रहेंगे। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटन को बढ़ावा: सांस्कृतिक धरोहर को संजोये हुए बुन्देलखण्ड अपनी गौरवशाली परंपरा एकता और आपसी भाई चारे के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड समृद्ध है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के बनने से पर्यटकों को देखने के लिए झाँसी का किला, ओरछा का किला, चतुर्भुज का मन्दिर, जहाँगीर महल, ओरछा वन्य जीव अभ्यारण, मध्य प्रदेश में पड़ने वाला खजुराहो आदि नजदीक पड़ते हैं। कालिंजर का किला, चित्रकूट धाम, भरतकूप, राजापुर, कालपी, महोबा, उरई, बटेश्वर आदि ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को देखने, दर्शन करने के लिए पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से बुन्देलखण्ड पर्यटन का हब बन रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोककला, लोकसंस्कृति, स्थानीय निर्मित वस्तुएं, दस्तकारी आदि को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आर्थिक प्रगति के साथ ही रोजगार में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय उत्पाद एवं रोजगार को मिलेगा बढ़ावा: बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलना शुरू हो गया है। आवागमन की अच्छी सुविधा होने पर क्षेत्रीय युवकों को स्वरोजगार के साथ-साथ स्थानीय हस्तकला, दस्तकारी, लोककला, पत्थर की मूर्तियों व खनन सामग्री आदि को बढ़ावा मिल रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से स्थानीय लोग सड़कों के किनारे विभिन्न तरह के खान-पान के लिए दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रानिक्स सामानों, स्थानीय खाद्य वस्तुओं, कृषि उपज, स्थानीय लोककला के बर्तन वस्त्र आदि बेचने की दुकानें खोलकर अपना धन्धा शुरू कर रहे हैं। उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ होगा। लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे एवं औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, फैक्टरियों आदि में भी कुशल, अकुशल श्रमिकों, तकनीशियनों, प्राविधिक शिक्षा प्राप्त युवाओं/युवतियों को नौकरियाँ मिलेंगी। इससे लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार का सृजन होगा। ईंधन की कम खपत व प्रदूषण में कमी: बुन्देलखंड एक्सप्रेस के बनने से वाहनों की गति में तेजी आ रही है

और वाहन घूमकर ज्यादा रास्ता तय कर अपनी मंजिल पर पहुँचने के बजाय एक्सप्रेस वे से उनकी मंजिल कम हो रही है और शीघ्र ही अपने गन्तव्य तक पहुँच रहे है। इससे वाहनों के ईंधन में कमी आ रही है और वाहनों के ईंधन में कमी से पैसा भी बच रहा है। अच्छी और गुणवत्तायुक्त सड़क से चलने पर ईंधन की खपत कम होती है। ज्यादा दूरी तक वाहन चलाने व जाम की समस्या होने पर वाहनों से ज्यादा धुआ निकलता है. इससे प्रदूषण बढ़ता है। किन्तु एक्सप्रेस-वे से कहीं जाम व गति में धीमापन न होने से प्रदूषण कम होगा। साथ ही सड़क किनारे वृक्षारोपण भी हो रहा है। इससे प्रदूषण और कम होगा।

देश व प्रदेश के अन्य एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी: बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से पूरा बुन्देलखंड क्षेत्र देश व प्रदेश की राजधानियों सहित अन्य प्रदेशों से भी सीधे जुड़ गया है। दिल्ली की दूरी जो चित्रकूट से 10 से 12 घन्टे पहुंचने का समय लगता था वह कम होकर 6-8 घंटे हो गया है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे में मिला है, फिर यह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेस-वे एवं पूर्ण रूप से निर्मित व संचालित गंगा एक्सप्रेस-वे में तथा कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा प्रयागराज जेवर आदि एयरपोर्ट सहित प्रदेश व देश के समस्त एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़ गया है। इससे आवागमन एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में शीघ्रता हो रही है। उद्योगों, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मेडिकल तथा शिक्षण संस्थाओं का निर्माण: बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश और देश की कनेक्टिविटी सीधे हो गई है। एक्सप्रेस-वे के किनारों पर उद्योगों, फैक्टरियों की स्थापना हो रही है। उनकी स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता है। उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा इससे उनकी आर्थिक प्रगति होगी। प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया है जिसके अंतर्गत नोयडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे पर विभिन्न प्रौद्योगिकी, तकनीकी एवं मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं आदि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी। इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना से छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी, उन्हें दूर नहीं जाना होगा, और अभिभावकों की आर्थिक बचत होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को नौकरियों व रोजगार मिलेंगे। प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं वहाँ के लोगों के विकास के लिए निर्मित किये गये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निश्चय ही क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आयेगी -सरिता वर्मा, सूचना अधिकारी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

अनाज भंडारण के लिए शाहबाद-अंबाला के बीच बनाया जाए बड़ा साइलो - मुख्यमंत्री सैनी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वेयरहाउस व साइलो उपलब्ध हों। इसके लिए संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द अनाज भंडारण की समस्या का स्थाई समाधान निकालें। उन्होंने निर्देश दिए कि अनाज भंडारण के लिए शाहबाद व अंबाला के बीच साइलो (विशाल वेयरहाउस) बनाने की योजना तैयार की जाए। श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदेश में अनाज भंडारण तथा पलवल व नूंह क्षेत्रों में जलापूर्ति के प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारीगण उपस्थित थे।

साइलो के लिए रेल व सड़क के बीच 100 एकड़ तक भूमि चिह्नित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों द्वारा अनाज उत्पादन के लिए दिन-रात मेहनत की जाती है। इस अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में वेयरहाउस भी होने आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शाहबाद व अंबाला के बीच किसी ऐसे स्थान पर साइलो (विशाल वेयरहाउस) के निर्माण की योजना बनाई जाए जो रेलवे लाईन व सड़क मार्ग के बीच हो। ऐसा करने से कम खर्च में पूरे देश के साथ साइलो की कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि साइलो के लिए रेलवे लाईन व सड़क के बीचों-बीच आवश्यकता अनुसार 100 एकड़ तक जमीन अधिगृहीत कर ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को जमीन अधिगृहण व साइलो निर्माण की योजना तैयार करने का कार्य एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए।

हिसार में फल-सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की कार्ययोजना पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के मद्देनजर वहां सब्जियों व फलों की काफी अधिक मांग है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को हिसार एयरपोर्ट के समीप भी एक साइलो अथवा बड़े वेयरहाउस की स्थापना की कार्ययोजना तैयार करने को कहा जहां सब्जियों व फलों का सुरक्षित भंडारण किया जा सके और इन्हें हिसार एयरपोर्ट के माध्यम से मिडिल ईस्ट में सप्लाई किया जा सके। ऐसा करके प्रदेश के सब्जी व फल उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों के अधिक दाम मिल सकेंगे।

नहरी पानी की जलापूर्ति की योजना बनाएं अधिकारी

जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पलवल व नूंह क्षेत्र के 108 गांवों तथा पुन्हाना नगर में ट्यूबवेल आधारित पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसलिए भूमिगत जलस्तर को बनाए रखने के लिए जमीन को रिचार्ज करने हेतु विभाग द्वारा 7 रैनी वेल व बूस्टिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस कार्य पर 765 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ-साथ जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल से जलापूर्ति की जाती है उन क्षेत्रों में नहरी पानी से जलापूर्ति की योजना बनाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में नूंह व पलवल एरिया में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और वहां जनता को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अनाज भंडारण तथा पलवल व नूंह क्षेत्र में जलापूर्ति के संबंध में किया मंथन

'एक पेड़ मां के नाम' योजना के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक पौधारोपण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 'एक पेड़ मां के नाम' योजना के माध्यम से अभी से बड़ी संख्या में पेड़ लगवाने शुरू कर दिए जाएं ताकि प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड लगवाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पौधों को समय पर पानी मिले ताकि वे पूर्ण विकसित हो सकें। इसके लिए अधिकारी समुचित कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे.गणेशन तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी डॉ. शालीन सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

आसाम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में महीपाल ढांडा की संगठन क्षमता बनी बड़ी ताकत

चंडीगढ़ । (संवाददाता) आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर एक नया राजनीतिक अध्याय रचा है। आसाम की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जहां स्थानीय नेतृत्व की मजबूत रणनीति रही, वहीं देश के विभिन्न रायों से पहुंचे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत भी अहम रही। इसी क्रम में हरियाणा के नेताओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने चुनाव के दौरान आसाम के कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा संभाला। उनकी रणनीतिक सोच और जमीनी पकड़ का असर चुनावी माहौल में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मधुर व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और कुशल वक्ता के रूप में पहचान रखने वाले महीपाल ढांडा ने आसाम में अपनी कार्यशैली के प्रभाव से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चकित किया। उन्होंने न केवल संगठन के भीतर समन्वय स्थापित किया, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा का संचार भी किया। महीपाल ढांडा ने अपने दौरे के दौरान सबसे पहले संगठन की आंतरिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पार्टी से नाराज और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को मनाकर दोबारा सक्रिय किया, जिससे जमीनी स्तर पर भाजपा की पकड़ मजबूत हुई। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के दर्जनों प्रभावशाली नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया, जिससे पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ढांडा की यह रणनीति भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई। जिन क्षेत्रों में पहले पार्टी कमजोर मानी जा रही थी, वहां भी कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठनात्मक मजबूती ने चुनावी समीकरण बदल दिए। यह जीत केवल आसाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा के राष्ट्रीय संगठन की ताकत और समन्वय क्षमता का भी प्रमाण है। विभिन्न रायों के नेताओं का एकजुट होकर काम करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना, भाजपा की चुनावी सफलता का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। हरियाणा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह योगदान न केवल राय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मजबूत संगठन और समर्पित नेतृत्व किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा ने यह संदेश भी दिया है कि यदि संगठन मजबूत हो और नेतृत्व सक्रिय, तो किसी भी राय में राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं।

हरियाणा में 11 मई से प्रदेशव्यापी पशु टीकाकरण महाअभियान का होगा आगाज़ -कृषि मंत्री

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राय के पशुपालकों के हितों और प्रदेश के पशुधन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आगामी 11 मई 2026 से पूरे राय में मुंहखुर और गलघोंटू जैसी घातक बीमारियों के विरुद्ध एक विशेष प्रदेशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य पशुओं को इन जानलेवा छूत की बीमारियों से बचाकर पशुपालकों को संभावित आर्थिक नुकसान से सुरक्षित करना है। श्री राणा ने बताया कि इस टीकाकारण अभियान में पशुपालकों की सुविधा के लिए विभाग की विशेष टीमें सीधे पशुपालकों के घर-द्वार पर पहुँचेंगी। पशुपालकों को अपने पशुओं को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विभाग के कुशल पशु चिकित्सक और सहायक घर-घर जाकर इस सेवा को सुनिश्चित करेंगे। सरकार के निर्देशानुसार, यह टीकाकरण-सेवा

पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि प्रदेश के छोटे से छोटे पशुपालक पर भी कोई आर्थिक बोझ न पड़े। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत 4 महीने से अधिक आयु की सभी गायों और भैंसों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले इन रोगों के लिए अलग-अलग टीके लगाए जाते थे, लेकिन अब हरियाणा देश का पहला और एकमात्र ऐसा राय बन गया है जहाँ इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए एक ही संयुक्त टीके का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पशुओं को बार-बार होने वाली पीड़ा से राहत मिली है और पशुधन का प्रबंधन भी सुगम हुआ है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक डॉ0 प्रेम सिंह ने बताया कि ने इस महा-अभियान की सफलता के लिए वैक्सीन के परिवहन और भंडारण हेतु पुख्ता इंतजाम किए हैं। टीकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटरों (डूफ्रिज) और कोल्ड चैन का विशेष प्रबंधन किया गया है। उन्होंने आह्वान किया कि वे इस अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। जब भी विभाग की टीम उनके गांव या घर पर आए, तो अपने सभी पात्र पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। पशुपालकों को समझना होगा कि समय पर किया गया

- कहा, पशुओं को जानलेवा छूत की बीमारियों से बचाना है मुख्य उद्देश्य

यह टीकाकरण न केवल उनके पशुधन को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश की डेयरी अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगा। उल्लेखनीय है कि मुंहखुर रोग एक खतरनाक वायरस के कारण होता है, जिससे पशुओं के मुंह और खुरों पर छाले पड़ जाते हैं, जिससे वे खाना-पीना छोड़ देते हैं और उनके दुग्ध उत्पादन व कार्य क्षमता पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं, गलघोंटू रोग एक गंभीर बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जिसमें पशु के गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में भारी तकलीफ के कारण चंद घंटों में ही पशु की मृत्यु हो सकती है। उन्होंने बताया कि अभियान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या औषधालय में संपर्क कर सकते हैं।

प्रदेश में कहीं भी पीने के पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी- श्रुति चौधरी

सरकार प्रदेशवासियों को पर्याप्त और स्वछ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी पीने के पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार प्रदेशवासियों को पर्याप्त और स्वछ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने यह बात आज सिंचाई विभाग एवं जन अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कही । श्रीमती चौधरी ने प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पंप लगाकर पानी के टैंकों को समय पर भरना सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संसाधनों या धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें, यदि किसी ने ड्यूटी में कोताही की तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने प्रदेश के नागरिकों से भी अपील की कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार करें।

उन्होंने कहा कि पानी एक अमूल्य संसाधन है, इसलिए इसका दुरुपयोग न करें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही इस्तेमाल करें, ताकि सभी को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हांसी ब्रांच में सोमवार 4 मई, 2026 को पानी छोड़ दिया गया था , यह पानी सुंदर सब ब्रांच होते हुए भिवानी शहर के पानी के टैंकों तक पहुंच गया है । इससे भिवानी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा।

नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं की सुविधा के व्यापक इंतजाम - राय निर्वाचन आयोग

चंडीगढ़ । (संवाददाता) हरियाणा राय निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आयोजित होने वाले आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मतदान केंद्रों पर साइनज, हेल्प डेस्क की विशेष सुविधाएं सुनिश्चित

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा सभी उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को सुगम एवं व्यवस्थित मतदान का अनुभव प्रदान किया जाए। इसके तहत मतदान केंद्रों पर स्पष्ट संकेतक (साइनज), हेल्प डेस्क, पेयजल, शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि मतदाता आसानी से अपने बूथ तक पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं अस्वस्थ मतदाताओं के लिए

दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश

प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर तथा अलग कतारों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के मतदान का अवसर मिल सके। प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं की सुविधा एवं गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए महिला स्टाफ की नियुक्ति, पृथक कतारें तथा आवश्यकतानुसार अलग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट-एड) की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा जरूरत पड़ने पर पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर भीड़ अधिक रहने की संभावना है, वहां विशेष प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ, वाहनों की उपलब्धता तथा एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों की सहायता ली जाएगी, ताकि कतारों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मतदाता कल्याण उपायों की निगरानी करेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

हैदराबाद हाउस- भारत और वियतनाम ने 13 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले पीएम मोदी?

नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने बुधवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले साल जब भारत से पवित्र बौद्ध अवशेष वियतनाम भेजे गए, तो डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों ने उनके दर्शन किए थे। हम चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखेंगे और इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा, एक दशक पहले वियतनाम की मेरी यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला व्यापक रणनीतिक साझेदार बना था। तब से हमारे संबंधों और हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। सभ्यताओं के साथ-साथ हमारे व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के संबंध भी मजबूत हुए हैं। इसी मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को आधुनिक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा, उन्होंने अपने भारत दौरे की शुरुआत बोधगया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। उनके इस दौरे और हमारी सार्थक चर्चाओं के माध्यम से हम अपनी आपसी सद्भावना को ठोस नतीजों में बदल रहे हैं। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी में विरासत और विकास, दोनों ही अहम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे भारत में राष्ट्रपति तो लाम का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और कई व्यापारिक दिग्गजों के साथ उनका भारत दौरा स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह भारत-वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।

दोनों देशों के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जो इस प्रकार से है-

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड और वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स (आईटीआरआरई) के बीच आपसी सहयोग पर समझौता।

भारत के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय के बीच 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वियतनाम के स्टेट बैंक (एसबीवी) के बीच भुगतान प्रणालियों और डिजिटल भुगतान में नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत औषधि प्रशासन (डीएवी) के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।

हार के बाद भी अडिग ममता- इस्तीफे से फिर किया इनकार, बोलीं- हटाना है तो हटा दे

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, अगर किसी को हटाना है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए।

उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

तृणमूल कांग्रेसके सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह बात कही। उन्होंने आरोप

लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उनके कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 1500 से अधिक टीएमसी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया।

ममता का आरोप- चुनाव नहीं, अत्याचार हुआ

ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव नहीं, बल्कि अत्याचार बताया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इन संस्थाओं ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में एकजुटता और मजबूत हुई है। ममता ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे संघर्ष जारी रखें और विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराएं।

विश्वासघात करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि वह इस हार को अंतिम नहीं मानतीं और आगे भी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के भीतर जो लोग विश्वासघात करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई।

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या- मध्यग्राम इलाके में चार गोलियां मारी

टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मर्डर का आरोप

कोलकाता । (वेबवार्ता) पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या की गई है। कोलकाता के मध्यग्राम इलाके में 4 राउंड फायरिंग हुई है। रथ की हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई। इनमें भाजपा और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ता हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

कांग्रेस ने राज्यपाल पर लगाया विजय को सरकार गठन से रोकने का आरोप, भाजपा पर भी साधा निशाना

चेन्नई । तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर माहौल गरमा गया है। इस बीच कांग्रेस नेता सेंथिलमलाई वोतिमणि ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टीवीके नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जो सही नहीं है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर लोक भवन के माध्यम से राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की।

बहुमत साबित करने का स्थान- विधानसभा, लोक भवन नहीं

कांग्रेस नेता वोतिमणि ने साफ कहा कि बहुमत साबित करने की असली जगह केवल विधानसभा है, न कि 'लोक भवन'। उनके मुताबिक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सरकार गठन की प्रक्रिया विधानसभा में ही पूरी होती है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और सबसे बड़ी पार्टी के नेता टीवीके के विजय को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए।

राज्यपाल की भूमिका पर सवाल, भाजपा पर आरोप

वोतिमणि ने कहा कि राज्यपाल का जनता के फैसले में बाधा डालना उचित नहीं है। उन्हें विश्वास है कि राज्यपाल राजनीतिक और संवैधानिक सिद्धांतों से अवगत हैं। उन्होंने भाजपा पर तत्काल लोक भवन के माध्यम से राजनीति बंद करने का आग्रह किया और राज्यपाल से टीवीके नेता विजय को तुरंत सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने की मांग की। यह बयान ऐसे समय आया है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस, जो टीवीके की सहयोगी है, राज्यपाल पर सरकार गठन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने और भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रही है।

बंगाल में हिंसा : 80 लोग गिरफ्तार; बिना इजाजत जुलूस पर रोक

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं, खास तौर से राज्य की राजधानी कोलकाता में विशेष व्यवस्था की गई है। इसको लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने बुधवार को प्रेस वार्ता भी की। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि, लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। उन्होंने आगे बताया कि, पुलिस हर स्थिति पर नजर रख रही है और जहां भी गड़बड़ी की कोशिश होगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि न्यूटाउन इलाके में जो घटना सामने आई है, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, यह मामला

दो गुटों के आपसी टकराव का है। इस दौरान कई जगहों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने यह भी बताया कि अब तक कुल 80 लोगों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे। कमिश्नर ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और पुलिस इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही है। जश्न और जुलूस को लेकर भी पुलिस ने साफ नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई बिना अनुमति के जुलूस निकालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने खास तौर पर कहा कि जश्न के दौरान जेसीबी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोलकाता में सीआरपीएफ की 65 कंपनियां तैनात हैं और 240 क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैयार हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और लोगों ने बिना किसी डर के मतदान किया। कोई बड़ी हिंसा या धमकी की घटना सामने नहीं आई है, केवल कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई।

कुर्सी पर अड़ीं दीदी- हार के बाद भी इस्तीफा नहीं, राउत ने दिया समर्थन, कहा- तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा

मुंबई । पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी का यह कदम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि यह केवल सत्ता का मोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई है। संजय राउत ने कहा कि देश में केंद्र की तानाशाही और चुनाव आयोग के पक्षपाती व्यवहार के खिलाफ एकजुट होना अब अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में चुनाव आयोग की आलोचना की। राउत ने आरोप लगाया कि वर्तमान में चुनाव संस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार की गुलाम बन चुकी है। उन्होंने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि भविष्य में चुनाव लड़ना भी है या नहीं।

जनादेश नहीं, यह तो एक गहरी साजिश है - ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने बंगाल के चुनावी नतीजों को जनता का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी को साजिश के तहत हराया गया। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 207 सीटें मिली हैं, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है। ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं, बल्कि पक्षपाती चुनाव आयोग से थी।

होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा न खोला गया तो ईरान पर बमबारी होगी, डोनालड ट्रंप की चेतावनी

इंटरनेशनल डेस्क । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलने की स्थिति में ईरान पर और ज्यादा बमबारी करने की बुधवार को चेतावनी दी। इस बीच, युद्ध खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के समझौते के करीब पहुंचने की खबर भी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियस की खबर में अमेरिकी अधिकारियों और दो अन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर एक पृष्ठ के सहमति पत्र को मंजूरी देने और विस्तृत परमाणु वार्ताओं के लिए एक रूपरेखा तय करने के करीब पहुंच गए हैं। खबर के अनुसार अमेरिका को

उम्मीद है कि ईरान अगले 48 घंटे के अंदर विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। हालांकि खबर में यह भी कहा गया है कि अभी कुछ तय नहीं है। खबर में कहा गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार दोनों पक्ष किसी समझौते के इतने ज्यादा करीब पहुंचे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, अगर ईरान पहले से तय शर्तों को मान ले तो इस समय जारी बड़ा सैन्य अभियान एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। समुद्री नाकाबंदी हट जाएगी और होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान समेत सभी के लिए खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने सहमति नहीं जताई, तो बमबारी शुरू होगी। यह बमबारी दुर्भाग्य से पहले की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर और बहुत तेज होगी। एक्सियस की खबर के अनुसार, इस समझौते में ईरान परमाणु संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमत होगा, जबकि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा देगा, साथ ही ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए धन के इस्तेमाल की अनुमति देगा। खबर के अनुसार दोनों देश होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों और व्यापार पर लगी पाबंदियों को भी कम या खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं। खबर में कहा गया है कि इस सहमति पत्र में बताई कई शर्तें तभी लागू होंगी जब दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौता हो जाएगा। खबर के अनुसार अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका बनी रहेगी, या स्थिति लंबे समय तक अनिश्चित बनी रह सकती है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के बाद चीन ने ईरान युद्ध में समग्र संघर्ष विराम की अपील की।

अराघची 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद से पहली बार चीन की यात्रा पर है।

एसी में हुए तेज धमाके, हिसार के 4 मंजिला होटल में भीषण आग...आसपास की बिल्डिंग खाली कराई

हिसार । हरियाणा के हिसार में रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित चार मंजिला होटल डिजायर में आग लग गई है। आग होटल के किचन से भड़की। देखते ही देखते आग होटल की चौथी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि होटल में लगे एसी फटने लगे। वहां मौजूद होटल स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके अलावा होटल की पार्किंग में खड़े वाहन आग की चपेट में आ गए। इसके बाद लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों को हटाया। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। होटल से सटी बिल्डिंग्स को भी एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया था। इस दौरान होटल से सटी बिल्डिंग में एक युवती भी फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने सड़क पर कंबल लगाकर दूसरी मंजिल से जंप करवाकर बचाया। इसी दौरान बिल्डिंग से गिरी ईंट महिला के सिर में लग गई। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 किमी दूर से धुएं का गुबार देखा गया। करीब दो से तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस होटल डिजायर में यह आग लगी, वह पॉश एरिया रेड स्क्वेयर मार्केट है। वहां कई कंपनियों के शोरूम, होटल और कॉमर्शियल बिल्डिंग है। होटल डिजायर हिसार के रामपुर के रहने वाले शुभम शर्मा का है, जिसमें 15 कमरे हैं। बुधवार शाम करीब चार बजे होटल के कीचन में शॉर्ट सर्किट से यह आग भड़की। उस वक्त वहां मौजूद 5 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने शोर मचाते हुए भाग कर जान बचाई।

गाजियाबाद में दिनदहाड़े फायरिंग कर एटीएम कैश वैन लूटी, ड्राइवर को बंधक बनाकर 25 लाख नकद लेकर बदमाश फरार

गाजियाबाद। शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर बदमाशों ने एटीएम कैश वैन को निशाना बनाते हुए बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने वैन को घेरकर ड्राइवर को बंधक बना लिया और करीब 25 लाख रुपये नकद लूट लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वारदात के दौरान बदमाशों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी दिल्ली नंबर की थी, जिससे बदमाशों के बाहरी होने की आशंका जताई जा रही है। लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर और वैन को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है और पूरे क्षेत्र में कांबिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में वैन में बड़ी रकम होने की बात सामने आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस दौरान तीन कर्मचारी और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है।

वैन को मसूरी थाना क्षेत्र से रिकवर किया गया है। कर्मचारी बयान बदल रहे हैं। ऐसे कर्मचारी भी शक के दायरे में है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ टीमों का गठन किया गया है। वैन को फोरेंसिक जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ले गई है।

कछ तट पर मिली संदिग्ध पाकिस्तानी नाव, बीएसएफ अलर्ट; जांच तेज, समुद्री सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा

अहमदाबाद । गुजरात के कछ जिले के समुद्री तट पर बुधवार को एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव परित्यक्त अवस्था में मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक, यह नाव भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास एक क्रीक क्षेत्र में मिली है। प्रारंभिक जांच के दौरान नाव में मछली पकड़ने के उपकरण मिले हैं, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि नाव को किसने और कब छोड़ा, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार, बीएसएफ के जवान नियमित गश्त के दौरान इस नाव तक पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल, अरब सागर के क्रीक क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन कई बार पाकिस्तानी मछुआरे अवैध रूप से भारतीय सीमा में

मछली पकड़ने के लिए घुस आते हैं। ऐसे मामलों में, जब वे बीएसएफ की गश्ती टीम को देखते हैं, तो अक्सर अपनी नाव छोड़कर वापस पाकिस्तान की ओर भाग जाते हैं। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

धंस गया एक्सप्रेसवे-गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर यातायात प्रभावित, बड़ा हादसा टला

गुरुग्राम । गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर एसडी आदर्श स्कूल के पास पुरानी मास्टर सीवर लाइन के कारण सड़क फिर एक बार और धंस गई है। यातायात पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और एनएचएआई ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सुभाष चौक से बादशाहपुर के पार तक करीब 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनी हुई है। एलिवेटेड रोड सुभाष चौक एसडी आदर्श स्कूल से शुरू होता है। सुभाष चौक के पास एलिवेटेड रोड के शुरू होने के प्वाइंट पर जीएमडीए की मास्टर सीवर लाइन टूटने से एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बुधवार को

धंस गया था। हाईवे निर्माण करते समय इस मेन सीवर लाइन को शिफ्ट नहीं किया जा सका था। करीब 30-35 साल पुरानी लाइन होने से अक्सर सड़क धंसने की समस्या आ रही है। इससे हाईवे पर यातायात प्रभावित होता है। एनएचएआई के अनुसार करीब 200 मीटर मास्टर सीवर लाइन एलिवेटेड रोड के दायरे में है। दूसरा इसे शिफ्ट करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। सर्विस रोड के बगल में स्कूल और वाहनों का काफी दबाव रहता है। जगह की कमी और वाहनों के दबाव के कारण अब लाइन को शिफ्ट करना संभव नहीं है। ऐसे में मास्टर लाइन को सीआईपीपी (क्योर्ड इन प्लेस पाइप) पद्धति से मरम्मत कराने की योजना। पहले जीएमडीए इसे ठीक करता आ रहा है। 5वीं बार भी सीवर लाइन को ठीक कराया था लेकिन इस बार फिर से सड़क धंस गई। जीएमडीए अधिकारी ने बताया कि धंसी सड़क वाली जगह को बैरिकेट कराया गया है।